rashtra. In the 1223 [MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*] present days of women upliftment and the Government's desire to better the lot of women in our country ,it is slur on the culture of India that prostitution exists in our country. The shameful and evil practice is still prevalent in the States of Maharashtra and Karnataka. The irony of this nefarious practice is that it is being done in the name of religion. The ignorant people offer teenage girls to the goddesses in the guise of religious ritual. The reality is that it helps the brothel-owners and pimps from cities to procure prostitutes. The pimps and unsocial elements visit these areas every year and persuade the parents to part with their daughters. These girls are called 'Jogtins'. They are accessible to any man and thus prostitution becomes an easy means of livelihood for the 'Jogtins'. These jogtins are in miserable plight. The Government should find ways and means to solve this evil problem. The law banning the Devdasi system should be strictly enforced. The Jogtins should be rehabilitated and further possibility of continuance of this evil should be strongly checked. As the subject falls under the purview of Central Government, I would urge the Government to take strong action otherwise this menace will continue to perpetuate.

(iv) STRIKE BY ALL INDIA UNIVERSITY EMPLOYEES FEDERATION

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के विश्वविद्यालय कर्मचारी अखिल भारतीय विश्व विद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से 10 दिसम्बर, 1980 को हड़ताल कर रहे हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की मांगों के साथ देश के एक सौ बीस विश्वविद्यालय के करीब एक लाख कर्मचारी हैं। उनके मांग पत्रों में अन्य बातों के अलावा न्यूनतम मजदूरी के सिद्धान्त पर आधारित वेतन में समरूपता मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता, समान सेवा शर्त, सीनेट और सिंडीकेट आदि में प्रतिनिधित्व शामिल हैं। 1969 में "दि नेशनल कमीशन आन लेबर तथा संसद की पैटीशन कमेटी" ने भी अनुशंसा की है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाय। उनके मांग पत्रों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को बिल्कुल खत्म करने पर तुली हुई है।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार विश्वविद्यालय कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जायज मांगों को स्वीकार करे।

(v) TRANSFER OF PASSENGER AND COASTAL SERVICES IN CERTAIN PARTS OF THE COUNTRY OF MUGHAL LINES LIMITED

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The shipping Corporation of India, which is a Central Government undertaking, at its Calcutta Office looks after the business of the Corporation so far as coastal service is concerned as well as the passenger service to Andaman & Nicobar Islands through its Passage and Coal Coastal Department (Calcutta). It is understood that the Government is considering to transfer its passenger services as well as coastal services to Mogul Lines Ltd., operating from Bombay. It is further learnt that few tramp vessels are going to be handed over to Mogul Lines. Ltd , from the shipping Corporation of India. Such a decision will be a retrograde step and will seriously affect the proper functioning of the Shipping Corporation of India. It has also raised genuine apprehension in the minds of the employees of the Shipping Corporation at Calcutta about loss of employment and transfer of existing employees from the Calcutta Office to Bombay which will seriouly affect them prejudicially and also will amount to change in conditions of service. Such action will further reduce the employment potentiality at the

[Shri Somnath Chatterjee]

Calcutta Office. The proposed move will also prejudicially affect the existing agreement with the employees through their recognised Union, viz., Shipping Corporation Employees' Union (Calcutta). I call upon the Government to desist from such a move, if there is any proposal to that effect and to make a statement allaying the apprehensions of the employees at the Calcutta office.

(vi) CRISIS IN MICA INDUSTRY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अभ्रक उद्योग गंभीर संकट से होकर गुजर रहा है। इसके छोटे व्यापारियों की लूट सबसे अधिक हो रही है। माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया अपने अभ्रक की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को इतना कम मूल्य दे रहा है कि वे अपने मजदूरों को सरकार द्वारा तै निम्नतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। फलस्वरूप हजारों मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न है। इस संकट से प्रभावित होकर अभ्रक मालिक हजारों मजदूरों की छंटनी भी कर रहे हैं।

12.24 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मिटको की अभ्रक व्यापार एवं मजदूर विरोधी इस नीति का परिणाम यह हो रहा है कि एक बड़ी संख्या में इसके व्यापारी इस उद्योग को छोड़कर भाग रहे हैं तथा बहुत से दूसरे व्यपारी अपने लाइसेंसों का दुरुपयोग कर अभ्रक के गैर कानूनी धंधे में लग गए हैं।

एफ० ए० एस० और मिटको द्वारा निर्धारित अभ्रक के मूल्यों में 25से 48.4 प्रतिशत तक का अन्तर है। मूल्यों के इस अन्तर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

माइका सिलटिंग	विदेशी मूल्य रु० पं०	मिटको मूल्य	मूल्यों में कमी
नं० 4 1/2 डी०एल०	49.96	37.50	25 प्रतिशत
नं० 5 डी०एल०	44.95	29.50	34.3 प्रतिशत
नं० 5 1/2 डी०एल०	15.89	10.25	35.4 ,,
नं० 6 डी० एल०	10.40	5.35	45.4 ,,
नं० 6 फर्स्ट लूज	8.27	5.00	39.5 ,,
नं० 6 इंटर लूज	7.08	4.55	35.6 ,,
नं० 6 सेकण्ड लूज	5.92	3.80	35.8 ,,
नं० 6 थर्ड लूज	4.72	3.07	35 ,,

इस चार्ट से यह स्पष्ट है कि एफ० एस० एस० और मिटको के मूल्यों में एम० एम० टी० सी० के जमाने के मूल्यों में दुगना से भी अधिक का अन्तर है। छोटे व्यापारियों की इस से बढ़कर लूट और क्या हो सकती है ?